Financial assistance to deep sea fishing industry

2107. SHRI SUBAS MOHANTY: Wli the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what steps are being TaTten to assist the deep sea fishing industry by nationalt-fed banks;

(b) whether it is a fact that he Banking department is directly supervisi ig loang for fishing trawlers since 1st Junf (1987;

(c) whether Government w II consider directing the new organisatioi under the Ministry to give liberal financid assistance to owners of deep sea fishing ti iwlers; and

(d) whether small entreprene irs can seek financial •assistance from this < rganisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (S IRI JAN A-RDHAN POOJARI); (a) RBI has issued general guidelines to all sche luled bank* for advances to priority sectc r, including fisheries. Advances to fisheries :over activities from fish catching to exj ort of fish, as well as financing of equipm :nt required for deep sea fishing. Financial assistance under priority sector is availabli from commercial banks by way of invest nent credit

(b) The Shipping Develop) lent Fund Committee which used to provide loans for deep sea fishing trawler$_s$ vas wound up with effect from 3rd April, 1987 and in accordance with the provisions >f the Ship ping Development Fund Comn ilte$_e$ (Abo lition) Act, 1986, the obligat ons of tha esrstwhile SDFC have bee$_n$ vested in the Central Govenment.

(c) and (d) The Shipping Credit and Investment Company of India has been set up i$_n$ December 1986 for providing finan cial assistance, *inter-alia,* for the acquistion of merchant shipping vessels a^{na} certain deep sea fishing trawlers. Proposals fox sanction of loans for above acquisitions ar« considered by SCICI, o$_D$ the merits of each tfase, based on the economic and technical viability of the project.

2108. *[Transferred to the* 18r/i *August,* 1987].

भूमिहीन श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा

2109. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा कर्ें कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जून, 1987 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार जीवन बीमा निगम, गुजरात में आठ लाख भूमिहीन श्रमिकों के सामूहिक बीमे से संबंधित कार्यवाही आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या यह कार्य बिहार तथा अन्य राज्यों में भी आरम्भ किया जाएगा ; और

(ग) क्या यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू है और यदि हां, तो जहां यह लागू है, उन राज्यों के नाम क्या हैं और वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। गुजरात सरकार ने पहली अप्रैल, 1987 से आठ लाख भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन बीमा निगम से ग्रुप बीमा पालिसी ली है। यदि राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं में भागीदार बनने की इच्छुक हों तो जीवन बीमा निगम को अन्य राज्यों (बिहार सहित) द्वारा इस प्रकार की ग्रुप बीमा योजनाएं प्रारम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर, जीवन बीमा निगम के परामर्श से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक बीमा योजना शीघ्र शुरू की जा रही है, जिसकी प्रीमियम लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों की प्राप्ति पर भारत की प्रतिक्रिया

2110. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम, प्रक्षेपास्त्र आदि हथियार प्राप्त किये जाने